

## कॉलेजियम सिस्टम

### प्रलिस के लयः

कॉलेजियम सिस्टम, भारत का मुख्य न्यायाधीश ।

### मेन्स के लयः

कॉलेजियम सिस्टम का वकलस और इसकी आलोजना ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने [सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली](#) की आलोजना करते हुए कहा क न्यायाधीश योग्यता को दरकनार कर अपने पसंद के लोगों की नयुकताया पदोन्नतकी सफारश करते हैं ।

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नयुकतासे संबंधत हैं ।

## कॉलेजियम प्रणाली और इसका वकलसः

- परचयः
  - यह न्यायाधीशों की नयुकता और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो [संसद](#) के कसी अधनियम या संवधान के प्रावधान द्वारा स्थापत न होकर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणयों के माध्यम से वकलसत हुई है ।
- कॉलेजियम प्रणाली का वकलसः
  - **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
    - इसने यह नरिधारत कयल क न्यायक नयुकतायों और तबादलों पर [भारत के मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार कयल जा सकता है ।
    - इस नरिणय ने अगले 12 वर्षों के लयल न्यायक नयुकतायों में न्यायपालका पर कार्यपालका की प्रधानता स्थापत कर दी है ।
  - **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की क "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमतल" है ।
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा क यह CJI की वयकतगत राय नहीं होगी, बल्क सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी ।
  - **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
    - राष्ट्रपतल द्वारा जारी एक प्रेजडेंशयल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय नकलय के रूप में कॉलेजियम का वसतार कयल, जसमें CJI और उनके चार वरषठतम सहयोगी शामिल होंगे ।

## कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुखः

- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरषठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं ।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरषठतम न्यायाधीश करते हैं ।
- उच्च न्यायपालका के न्यायाधीशों की नयुकता कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रयल में सरकार की भूमकल कॉलेजियम द्वारा नाम तय कयल जाने के बाद की प्रक्रयल में ही होती है ।

## वभनन न्यायक नयुकतायों के लयल नरिधारतल प्रक्रयलः

- भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) के लयलः

- CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अगले CJI के संदर्भ में नविवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सफारिश करता है।
- हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतर्लघन वविाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये वरषिठता के आधार का पालन किया जाता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
  - CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरषिठत न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है।
  - नरिधारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करानी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
  - इसके पश्चात् कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये:**
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा।
  - यद्यपि चयन का नरिणय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफारिश CJI और दो वरषिठत न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
  - हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के नविवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरषिठत सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
  - यह सफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिये राज्यपाल को सलाह देता है।

## कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **कार्यपालिका का बहिष्करण:** न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया से **कार्यपालिका** के पूर्ण बहिष्करण ने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया है जहाँ कुछ न्यायाधीश पूर्ण गोपनीय तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
- इसके अलावा, वे किसी भी प्रशासनिक नकियाय के प्रता जवाबदेह नहीं होते हैं जिसके कारण सही उम्मीदवार की अनदेखी करते हुए गलत उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है।
- **पक्षपात और भाई-भतीजावाद की संभावना:** कॉलेजियम प्रणाली CJI पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई वशिषिट मानदंड प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद (Favouritism and Nepotism) की व्यापक संभावना की ओर ले जाती है।
  - यह न्यायिक प्रणाली की गैर-पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में वधि एवं व्यवस्था के वनियिमन के लिये अत्यंत हानिकारक है।
- **नरित्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के वरिद्ध:** इस प्रणाली में नरित्रण एवं संतुलन के सिद्धांत (Principle of Checks and Balances) का उल्लंघन होता है। भारत में व्यवस्था के तीनों अंग-वधियायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यूँ तो अंशतः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नरित्रण के साथ ही संतुलन भी बनाए रखते हैं।
  - कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है, जो नरित्रण का बहुत कम अवसर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है।
- **‘कलोज़-डोर मैकेनिज़म :** आलोचकों ने रेखांकित किया है कि इस प्रणाली में कोई आधिकारिक सचवालय शामिल नहीं है। इसे एक ‘कलोज़ डोर अफेयर’ के रूप में देखा जाता है, जहाँ कॉलेजियम की कार्य प्रणाली और नरिणयन प्रक्रिया के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती।
  - इसके अलावा कॉलेजियम की कार्यवाही का कोई आधिकारिक कार्यवृत्त भी दर्ज नहीं होता।
- **असमान प्रतनिधित्व:** चिता का एक अन्य क्षेत्र **उच्च न्यायपालिका की संरचना** है, जहाँ महिलाओं का प्रतनिधित्व काफी कम है।

## नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास:

- इसे **‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’** (99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से) द्वारा प्रतस्थापित करने के प्रयास को 2015 में ने इस आधार पर खारजि कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा है।

## आगे की राह

- कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हुए **रक्तियों को भरना एक सतत् व सहयोगी प्रक्रिया है तथा इसके लिये कोई समय-सीमा नहीं हो सकती है।** हालाँकि यह एक स्थायी, स्वतंत्र नकियाय के बारे में सोचने का समय है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये न्यायिक प्रधानता की गारंटी देता है लेकिन न्यायिक वशिषिटता की नहीं।
- इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिये, वविधिता को प्रतबिबिति करना चाहिये, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: नमिनलिखित कथनों पर वचिार कीजिये: (वर्ष 2019)

1. भारत के संवधान में 44वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से परे रखने वाला एक अनुच्छेद पेश किया।
2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में भारत के संवधान में 99वें संशोधन को रद्द कर दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- यह वर्ष 1975 में संविधान का 39वाँ संशोधन था, जिसके माध्यम से संसद ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावों के संबंध में याचिकाओं पर नरिणय लेने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को खत्म करने के लिये एक अनुच्छेद पेश किया। इसके बजाय संसद द्वारा गठित एक निकाय को ऐसे चुनावी विवादों को हल करने की शक्ति प्राप्त होगी। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- 99वें संविधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिये प्रावधान किया, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेगा। इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' के सिद्धांतों के साथ-साथ 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांतों को प्रभावित करता था। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

प्रश्न: भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2017)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/collegium-system-7)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/collegium-system-7>

